प्रकाशनार्थ

पटना, 6 दिसंबर, 2019. आद्री स्थित इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) द्वारा बिहार सरकार के महिला विकास निगम और सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज (सी3) के साथ मिलकर आयोजित किए गए 'लैंगिक समानता में कमी : स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसर' शीर्षक दो–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अतिथियों को संबोधित करते हुए बिहार के माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लैंगिक असमानता सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण से कम नहीं होगी। इसके बजाय हमें शिक्षा पर अधिक खर्च करने और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और शराबबंदी जैसी बहुदिशाई रणनीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल 1940 के दशक में और आबादी के बाद भी अपने राजस्व का एक–चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता था जबकि बंबई राज्य का शिक्षा व्यय बिहार से पांचगुना था। शिक्षा से हिंसा के साथ–साथ कुल प्रजनन दर में भी कमी आती है। उनका कहना था कि लोग बदलाव चाहते हैं इसलिए कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो स्थिति में बदलाव ला सकें। उन्होंने स्कूली लड़कियों के लिए साइकल योजना जैसे तीन–चार कार्यक्रमों का उल्लेख किया और कहा कि सिर्फ कानून नहीं वरन् समाज सुधार आंदोलन की जरूरत है।

डीएफआइडी इंडिया के प्रधान श्री गेविन मैकगिलिव्राय ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में लोगों के गलत विचारों को सही करने से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की समस्या दूर की जा सकती है। उन्होंने एक स्कूली छात्रा का उल्लेख किया जो चाहता था कि स्कूल विद्यार्थियों को सिखाएं कि लड़कियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कैसे करें। वहीं, विश्व बैंक के मार्टिन रामा ने दशम आइजीसी–इंडिया वार्षिक व्याख्यान देते हुए लैंगिक अंतराल का, खासकर भारत के संदर्भ में व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया और हम लैंगिक अंतराल दूर करने के लिए नीतियों के बारे में जो सोचते हैं उसकी समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने भारत और बिहार में महिला श्रमिकों का मामला भी उठाया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि महिलाओं के लिए उपयुक्त कार्यों की कमी और पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रचलनों (कि महिलाओं को काम करने बाहर नहीं जाना चाहिए) के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की भागीदारी घट रही है। भारत में लैंगिक समानता का सकारात्मक पक्ष यही है कि यहां 13 प्रतिशत विमानचालक महिलाएं हैं।

अपना विशेष वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निदेशक श्री अलकेश बाधवानी इसके बारे में बात करना चाहते थे कि यह कैसे देखा जाय कि लैंगिक समानता में कमी लाने वाले कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के कारण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में 38 से 55 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। प्रचलनों और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए मोबाइल फोनों का उपयोग किया जा सकता है और आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए मोबाइल फोनों के उपयोग के जरिए लैंगिक समानता हासिल करने के लिए फाउंडेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय और जीविका के साथ साझेदारी की है। उन्होंने लैंगिक मुद्दों पर बढ़–चढ़कर काम करने के लिए बिहार की प्रशंसा की।

बिहार सरकार के महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक डॉ. एन. विजयलक्ष्मी (भाप्रसे) ने रेखांकित किया कि बिहार में बाल विवाह की दर 69 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत और कुपोषण की दर 55 प्रतिशत से गिरकर 48 प्रतिशत रह गई है।

अतिथियों का स्वागत करते हुए आद्री के सदस्य सचिव और आइजीसी–इंडिया के बिहार लीड डॉ. शैबाल गुप्ता ने भारत जैसे विकासशील देश में विकसित देशों से भी अधिक लैंगिक अंतराल की ओर संकेत किया और कहा कि बिहार ने लैंगिक विषमता में कमी लाने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया है।

आइजीसी–इंडिया के कंट्री डायरेक्टर श्री प्रनब सेन ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में भी लागू होने लायक हैं।

बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की आनंदी मणि ने अपनी वार्ता में बताया कि कैसे गरीबी लोगों की पसंदों और व्यवहार को प्रभावित करती है। गरीबी और आय संबंधी अनिश्चितता के साथ काम के भारी बोझ के कारण महिलाएं डिप्रेशन से अधिक पीड़ित होती हैं।

'महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण : बाधाएं और समाधान' विषय पर आयोजित भोजनोपरांत सत्र के पैनल डिस्कशन में रेखांकित किया गया कि सशक्तीकरण लैंगिक अंतराल में कमी लाने की कुंजी है और इस फासले में कमी लाने पर चर्चा महिलाओं ही नहीं, उन सारी हस्तियों के बारे में होनी चाहिए जिनके बीच भारी अंतराल दिखता है। घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं के मामले में घरेलू हिंसा के साथ सकारात्मक सह–संबंध देखा गया है। सामाजिक प्रचलनों में बदलाव लाने के लिए वयस्कों से ध्यान हटाकर बच्चों और युवाओं को फोकस करना होगा। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने की जबकि संचालन सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज की सुश्री निवेदिता मेनन द्वारा किया गया। इसके पैनल में विश्व बैंक की गिरिजा बोरकर, साओ पाओलो विश्वविद्यालय के जोनाथल फिलिप्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तनुश्री गोयल, वर्जिनिया विश्वविद्यालय की शीतल सीकरी, विश्व बैंक की शुभा चक्रवर्ती और आइआइएम–अहमदाबाद के तरुण जैन शामिल थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की देवकी जैन द्वारा विशेष व्याख्यान–2 प्रस्तुत किया गया। सत्र की अध्यक्षता आइजीसी–इंडिया के कंट्री डायरेक्टर डा. प्रनब सेन ने की।

जेंडर और श्रम पर एक अन्य पैनल डिस्कशन का लक्ष्य इस बात पर हमारी समझ में गहराई लाना कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्या बात मायने रखती है और क्या चीज कारगर होती है और उन्हें सकारात्मक स्वस्थ दिशा में ले जाना था। इस चर्चा के केंद्र में बिहार का सक्षम इनिशिएटिव फॉर ह्वाट वर्क्स के मूल प्रश्न शामिल थे जिसे सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज (सी3) और उसके साझीदारों ने प्रस्तुत किया। उसमें श्रमशक्ति में महिलाओं की घटती भागीदारी, उनकी सुरक्षा, आवागमन, और महिलाओं का कौशल विकास कैसे हो जैसी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही, उसमें सशक्त एजेंसियों का निर्माण कैसे किया जा सकता है और उससे जुड़े सूक्ष्मार्थिक और वृहदार्थिक, दोनो प्रकार के प्रश्नों को भी देखा गया था। पुरुष और महिला, दोनो को प्रभावित करने वाले मांग और आपूर्ति संबंधी कारक, आय की उपलब्धता और अच्छी गुणवत्ता वाले काम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस पैनल का संचालन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सुश्री यामिनी आत्मविलास ने किया और इसके पैनल में आद्री की अश्मिता गुप्ता, अशोका विश्वविद्यालय के अश्विनी देशपांडे, आइएसआइ–दिल्ली की फरजाना आफरीदी, आइसीआइडब्ल्यू की नीलांजना सेनगुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शेर सिंह वेरिक और मेरीलैंड विश्वविद्यालय की सोनल दे देसाई शामिल थीं। सत्र की अध्यक्षता आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने की।

(अंजनी कुमार वर्मा)

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org